(6) तकनीकी ज्ञान का आयात तथा रायल्टी/तकनीकी ज्ञान संबंधी शुल्कों की अदायगी ;

(7) व्यापारिक कार्य के लिए विदेश-यात्रा ; और

(8) विदेशों में कार्यालयों की स्थापना तथा प्रतिनिधियों को रखना ।

इन सिफारिशों पर, रिजर्व बैंक, निर्यात आयात बैंक, निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम और सरकार के द्वारा विचार किया जा रहा है ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

Excise Duty Collection from Tiny and Cottage Match Units

6814. SHRI S. A. DORAI SEBASTIAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the amount of excise duty collected on the matches produced by the tiny and cottage match units during the past 3 years (year-wise) ;

(b) the amount of excise duty collected on the matches produced by the small scale middle sector match units during the past 3 years (year-wise) ; and

(c) the amount of excise duty from the mechanised sector during the past 3 years (year-wise) ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S. M. KRISHNA) : (a), (b) and (c) The information with regard to the amount of central excise duty collected during the financial years 1981-82, 1982-83 and 1983-84 from tiny and cottage match units paying duty @ Rs. 1.60 per gross, middle sector match units paying duty @ Rs. 4.50 or Rs. 5.50 per gross, and mechanised sector match units paying duty @ Rs. 7.20 per gross (the rates being liable for suitable adjustments, depending upon use of cardboard in match boxes) is being collected, and the same will be laid on the Table of the House.

जीरे का आयात

6815. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1983-84 के दौरान निर्यात किए गए जीरे की देश-वार मात्रा और मूल्य क्या था;

(ख) क्या 1984-85 के दौरान भी इसके निर्यात का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री० पी० ए० संगमा) (क) से (ग) इस समय जीरे का निर्यात खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत है । 1983-84 के दौरान अनुमानित निर्यात 7.59 करोड़ रु० मूल्य के 4605 मे० टन के हुए हैं । जीरे का निर्यात बहुत से देशों को किया जाता है यथा ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, नीदरलैंड फ्रांस, अल्जीरिया, ब्राजील हांगकांग, सिंगापुर, यूनान, सऊदी अरब तथा संयुक्त अरब अमीरात आदि ।

Turning of Mithila and Madhubani Regional Rural Banks into Pilot Regional Rural Banks

6816. SHRI BHOGENDRA JHA : Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the replies given to Unstarred Question Nos. 712 and 861 on 18 November, 1983 regarding limit

of advance credits by Regional Rural Banks and turning of Madhubani and Darbhanga Regional Rural Banks into Pilot Regional Rural Banks respectively and state :

(a) whether two or even one Regional Rural Bank like Mithila and Madhubani Regional Rural Banks can be turned into pilot banks for only productive self-employed endeavours with demonstrative results ; if so, details thereabout ;

(b) if not, the reasons therefor ; and

(c) how many applications for productive self-employed endeavours recommended by District Industries Centre or applied formally trained youth in goatery, paultery etc. or for gas and electric welding are pending disposal with Madhubani and Mithila Regional Rural Banks for more than four months ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHANA POOJARY) : (a) and (b) Regional Rural Banks extend credit support to all viable economic activities of eligible borrowers within their area of operation. These cover all sectors of the economy. It is not considered adviseable to restrict any Regional Rural Bank's lending to primary and secondary seetors only as it would mean denial of assistance to a large number of eligibre persons who may be earning or can earn their livelihood through viable ventures in the tertiary sectors.

(c) Information to the extent available will be collected and laid on the Table of the House.

देश में सैनिक स्कूलों को वित्तीय और प्रशासनिक जिम्मेदारियां

6817. **श्री दौलत राम सारण** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सभी 18 सैनिक स्कूलों की वित्तीय और प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक तथा यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कठिनाई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सैनिक स्कूल चित्तौड़ गढ़ राजस्थान के अध्यापकों के वेतनमान बढ़ाने, छात्रों को छात्रवृत्ति की धनराशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने तथा केन्द्रीय सरकार से छात्रवृत्ति की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान करने, छात्रावास व्यवस्था में उचित सुधार करने तथा छात्रों के लिए चिकित्सीय उपचार की व्यवस्था करने के लिए कोई प्रभावशाली कदम उठाने का है; यदि हां, तो कब तक और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; तथा इस सम्बन्ध में प्रतिवर्ष कितनी धन राशि खर्च होगी; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई निर्देश जारी किए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

सैनिक स्कूल सोसाइटी की योजना के अनुसार राज्य सरकारों को सैनिक स्कूल स्थापित करने के लिए सभी पूंजीगत व्यय वहन करना होता है तथा उनके आवर्ती अनुरक्षण के लिए निधि की भी व्यवस्था करनी होती है । व्यय में केन्द्रीय सरकार